आज़ादी का अमृत महोत्सव

साप्ताहिक सूचना पत्र

(दिनांक 13.08.2023 से 19.08.2023)

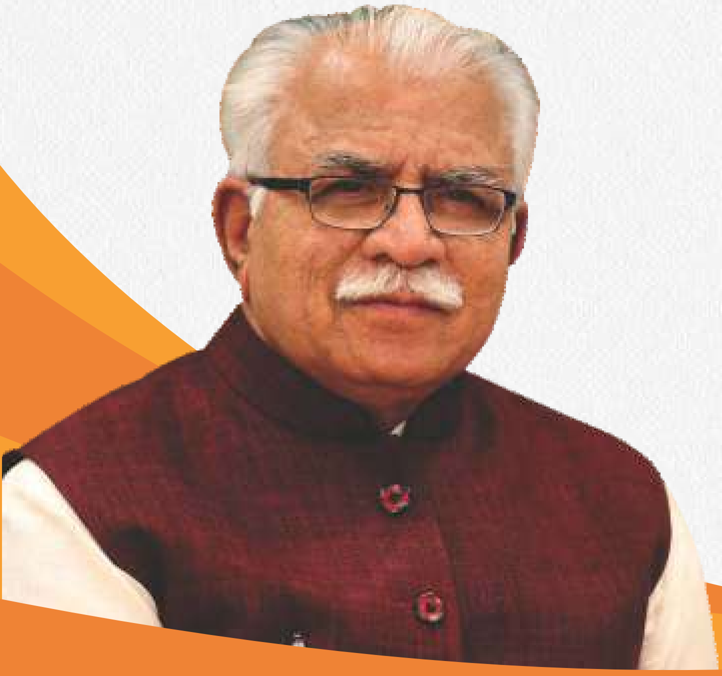

भारतीय जनता पार्टी
हरियाणा

करनाल जिला के गांव दनियालपुर में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन

(दिनांक 13.08.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी आज अपने करनाल जिला के गांव दनियालपुर में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याओं का समाधान करने के वक्त कहा कि प्रदेश में लोगों की आय में इजाफा करने और रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के लिए लगातार कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब प्रदेश के प्रत्येक गांव में सांझी डेयरी योजना लागू करके लोगों की आय को बढ़ाने का काम किया जाएगा। इस डेयरी के लिए प्रत्येक गांव में 1 या 2 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। सांझी डेयरी के लिए प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोग उनके परिवार के सदस्य है इसलिए एक–एक व्यक्ति के लिए रोजगार, बच्चों की पढ़ाई

साप्ताहिक सूचना पत्र

आदि विषयों की चिंता करना उनका कर्तव्य है। उन्होंने सरकार द्वारा जनहित में उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लोगों को घर बैठे सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। सरकार ने जहां आयुष्मान कार्ड योजना के तहत लोगों के स्वास्थ्य के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई है वहीं सरकार दयालु योजना के तहत 25 से 45 आयु वर्ष के व्यक्ति की मृत्यु पर 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने गांव के विकास पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा देते हुए कहा कि गांव के विकास पर अब तक पंचायत के माध्यम से 1 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। उन्होंने ग्राम पंचायत की मांगों को पूरा करते हुए गांव दलियानपुर से डबराना तक डेढ़ किलोमीटर रास्ते को पक्का करने की घोषणा की।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गांव दनियालपुर में सब हैल्थ सेंटर व बारात घर के अलावा गांव की गलियों, नालियों के साथ–साथ अन्य कार्यों पर 50 लाख का बजट खर्च किया जाएगा। उन्होंने जनसंवाद में बसंत विहार गली नम्बर 1 में प्रदूषण करने वाली फैक्ट्री की जांच करने, एक व्यक्ति की मुगल कनाल में बूथ का लम्बित जुर्माना माफ करने के आदेश दिए। जनसंवाद कार्यक्रम में एक अन्य व्यक्ति द्वारा रखी गई समस्या पर बोलते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार ने अवैध कालोनियों में रजिस्ट्रीयां बंद की है, इसके अलावा 7–ए स्कीम में भी रजिस्ट्रीयां नहीं होंगी।

करनाल में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन

(दिनांक 14.08.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाइ में करनाल शहर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा शुरू होने से पहले उन्होंने कहा कि आजादी बहुत संघर्षों और बलिदान के बाद मिली है। हमारे देश के अनगिनत लोगों ने अपने प्राणों की शहादत दी है, तब हमें आजादी मिली है। हम इस आजादी को कायम रखने के लिए संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। इसी वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देशभर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में करनाल में तिरंगा यात्रा निकाली गई। उन्होंने समस्त करनाल और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई व शुभकामनाएं दी। तिरंगा यात्रा के लिए बड़ी संख्या में

लोग रामलीला ग्राउंड में पहुंचे। सभी अपने हाथों में तिरंगा लिए हुए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने तिरंगा यात्रा की अगुवाई की। यात्रा रामलीला ग्राउंड से शुरू हुई। इस के बाद महर्षि वाल्मीकि चौक से कर्ण गेट के सामने से होते हुए सब्जी मंडी चौक पहुंची। इस दौरान बाजार में लोग हाथों में फूल लिए खड़े थे और यात्रा पर फूलों की वर्षा कर रहे थे।

तिरंगा यात्रा जैसे–जैसे शहर के अंदर से गुजरी भारत माता के जयकारों से शहर की गलियां गूंज उठी। इसके बाद यात्रा नेहरू प्लेस की तरफ बढ़ी, वहां पर कहीं बच्चों ने तो कहीं बुजुर्गों ने स्वागत किया। यहां से यात्रा महावीर दल फिर सनातन धर्म मंदिर होते हुए कर्ण स्वीट्स तक पहुंची। इसके बाद पुराना बस अड्डा होते हुए वापिस रामलीला ग्राउंड पहुंची।

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस

(दिनांक 14.08.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज फतेहाबाद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर कहा कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बंटवारे की त्रासदी झेलने वालों के बलिदानों के कारण आज हम सभी खुली हवा में साँस ले रहे हैं। आज के दिन अपनी शहादत देने वाले लोगों को याद करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन भारत के बंटवारे का दुखद दिन है। वर्ष 1947 में भारत की आजादी की प्रक्रिया चल रही थी तो आज के दिन भारत माता की छाती पर लकीर खींच कर देश का विभाजन भी किया गया था। हमें आजादी तो मिली लेकिन इस आजादी की हमें भारी कीमत चुकानी पड़ी। पूर्व की सरकारों ने कभी

शहादत देने वाले लोगों को याद करने की ओर ध्यान नहीं दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की पहल शुरू की।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के बंटवारे को 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी कहा और 15 अगस्त, 2021 को स्वतंत्रता दिवस पर आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ करते हुए इस विभाजन में अपनी जान गवाने वाले लोगों की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की थी।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पंचनद संस्था ने पिछले 15 सालों से विभाजन के पीड़ितों को याद करने का जिम्मा उठाया। पंचनद स्मारक ट्रस्ट द्वारा कुरुक्षेत्र में देश का विश्व स्तरीय शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है। हालांकि, सरकार की ओर से इस कार्य के लिए वित्तीय सहायता की बजाय समाज के लोगों से सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा कि पंचनद स्मारक ट्रस्ट द्वारा बनाए जा रहे स्मारक

में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि वे स्वयं अपने संपर्क से समाज के लोगों के सहयोग से साढ़े 5 करोड़ रुपये की राशि इकठ्ठा करके देंगे। इसके अलावा, उन्होंने विधायक श्री सुभाष सुधा, श्री विनोद भयाना, श्रीमती सीमा त्रिखा, श्री प्रमोद विज सहित 11 लोगों की ओर से 51–51 लाख रुपये के सहयोग की भी घोषणा की। उन्होंने पंचनद स्मारक ट्रस्ट, फतेहाबाद को भी अपने ऐच्छिक कोष से 21 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। इसके अलावा, शिवधाम नवीनीकरण योजना के तहत स्थानीय शिवपुरी शमशान घाट के लिए भी 21 लाख रुपये की राशि को मंजूर करने की घोषणा की।

स्वतंत्रता दिवस समारोह

(दिनांक 15.08.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज मंगलवार को आजादी की 76वीं वर्षगांठ पर फतेहाबाद में आयोजित राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की तथा राष्ट्रगान की धुन के साथ ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि वर्ष 2047 तक हरियाणा राज्य पूरे देश में विकास के मामले में सर्वोच्च स्थान पर होगा। देश की आजादी में योगदान एवं बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को याद किया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले उन्होंने लघु सचिवालय के समीप स्थित शहीदी स्मारक पर वीर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें नमन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा के वीरों ने भी

आजादी के आंदोलन में बढ़–चढ़ कर भाग लिया था। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भी वर्ष 1962, 1965 व 1971 के विदेशी आक्रमणों और आप्रेशन कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की नई मिसाल पेश की है। उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि वे आजादी के लिए मर–मिटने वाले ज्ञात–अज्ञात शहीदों के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आजादी का यह पावन पर्व उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन भी है। आज भारत अपनी उन्नत प्रौद्योगिकी और प्रतिभा के बल पर चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन शुरू कर रहा है। हाल ही में हमारा चन्द्रयान–3 चांद की कक्षा में प्रवेश कर चुका है और आज से एक सप्ताह बाद चांद पर उतरेगा।

उन्होंने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को दूरगामी विजन वाला प्रधानमंत्री बताते हुए कहा कि मोदी जी ने कई चुनौतीपूर्ण विवादों का चुटकियों समाधान कर दिया। जम्मू एवं कश्मीर

से अनुच्छेद–370 व धारा 35–ए को हटाकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत का सपना साकार किया है। अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य

मंदिर का निर्माण शुरू कर करोड़ों देशवासियों की आस्था को मजबूती दी है, जो अब पूरा होने को है। उन्होंने कहा कि हम पिछले 2 सालों से आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस महोत्सव के समापन पर इस बार माननीय प्रधानमंत्री ने मेरी माटी–मेरा देश अभियान चलाया है। गत 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर शुरू किये गए इस अभियान में देश के हर गांव व हर शहर की मिट्टी एकत्रित की जा रही है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के बंटवारे को 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी बताते हुए उसके पीड़ितों की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाना शुरू किया है। वन रैंक–वन पेंशन की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करके वीर सैनिकों का मनोबल बढ़ाया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर 21वीं सदी का आत्मनिर्भर भारत बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है, वर्ष 2025 तक ही इस नई नीति को पूर्ण रूप से लागू करने का

लक्ष्य रखा है। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उठाए गए अन्य कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि सर्जिकल एयर स्ट्राइक, नागरिकता संशोधन कानून, तीन तलाक की कुप्रथा से मुक्ति, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ अभियान, जल संरक्षण आदि अनेक युग–परिवर्तनकारी कदम उठाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि देश की आजादी से लेकर लम्बे समय तक पूर्व की सरकारें गरीब कल्याण की बातें तो करती रहीं, लेकिन लाभ नहीं दिया। हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन के अनुरूप प्रदेश के सभी परिवारों का पहचान पत्र बनाया, जिससे पात्र परिवारों की पहचान सुनिश्चित कर व्यवस्था का रुख सबसे गरीब की तरफ मोड़ा। उन्होंने कहा कि कुछ विपक्षी लोग बेशक पोर्टल पर सवाल उठाते हैं लेकिन इसी का परिणाम है कि आज घर बैठे गरीब की बेटी की शादी का शगुन, बुजुर्ग, विधवा व दिव्यांगों की पेंशन, बीपीएल कार्ड, चिरायु कार्ड, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति आदि लाभ एक क्लिक पर सीधे उनके खातों में जाते हैं। इस तरह हमने सरकार के खजाने को सीधे लाभार्थियों

के खाते से जोड़ दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब बिचौलिया संस्कृति खत्म हो गई है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। अब कोई भी व्यक्ति चाहे वह गरीब है, किसान है, व्यापारी है, महिला है, युवा है, आदि हर वर्ग की योजनाओं के मापदंडों और उनके लाभ को एक क्लिक पर देख सकता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 को हम अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मना रहे हैं। इसमें गरीबों के मुफ्त ईलाज के लिए लगभग 85 लाख आयुष्मान भारत–चिरायु कार्ड घर बैठे ही बनाए गए हैं। निरोगी हरियाणा

साप्ताहिक सूचना पत्र

योजना में लगभग 25 लाख गरीबों के स्वास्थ्य की जांच की है। हर घर नल से जल कार्यक्रम में 13 लाख घरों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाया है।

हमने गरीबों का जीवन–स्तर ऊपर उठाने के लिए अंत्योदय मेले लगाकर 50 हजार से अधिक गरीबों को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान किए हैं। गरीबों के सिर पर छत उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 36 हजार मकान बनाए गए हैं तथा 16 हजार मकान निर्माणाधीन हैं। हमने हर गरीब को राशन वितरण सुनिश्चित करने के लिए राशन डिपुओं पर पीओएस मशीनें लगवाई हैं। अब कोई भी व्यक्ति फर्जी तरीके से राशन प्राप्त नहीं कर सकता।उन्होंने कहा कि गरीबों का अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का सपना साकार करने के लिए चिराग योजना चलाई गई है। उन्हें कई तरह की छात्रवृतियां भी दी जाती हैं। सरकारी नौकरियों में गरीब परिवारों के उम्मीदवारों को 5 अतिरिक्त अंक दिये जा रहे हैं। यही नहीं, कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कच्चे कर्मचारियों की भर्ती में भी गरीब परिवारों के युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। अब 40 साल से अधिक आयु के विधुर और 45 साल से अधिक आयु के अविवाहित भी 2750 रुपये मासिक पेंशन के पात्र हो गए हैं।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मानव समाज के निर्माण और विकास में महिलाओं का बड़ा योगदान है। हम इस आधी आबादी का आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास करने व उन्हें सुरक्षित परिवेश मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने गांवों के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया है। महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए एक–तिहाई राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान किया गया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन व वीटा बिक्री केन्द्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया

है। स्वरोजगार के लिए महिलाओं के 56 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन भी किया गया है। बेटियों को उच्चतर शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए हमने 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज स्थापित किया है। प्रदेश में 76 नए कॉलेज खोले गए हैं।

उन्होंने बताया कि हमने शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए भी कई कदम उठाए हैं। करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला के विकास के लिए मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है, हिसार में भी यह अथोरिटी बनाएंगे। शहरों की हर संपत्ति की प्रॉपर्टी आई.डी. बनाई है। उन्होंने प्रदेश के लोगों से अपनी महान सांस्कृतिक परम्पराओं और उच्च नैतिक मूल्यों पर चलते हुए सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक व साम्प्रदायिक भेदभावों को भुलाकर आपसी प्रेम–प्यार व भाईचारे को बनाए रखने का आहवान किया।

इस अवसर पर समारोह में विभिन्न स्कूली बच्चों ने देश भक्ति के साथ साथ हरियाणवी, पंजाबी व देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तूति दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समारोह में भाग लेने वाले बच्चों के लिए पांच लाख रुपये देने की घोषणा की।

सिरसा लोकसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं प्रबुद्ध नागरिकों से मुलाकात

(दिनांक 16.08.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिरसा लोकसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं प्रबुद्ध नागरिकों के साथ मंत्रणा की और कहा कि आप खुलकर अधिकारियों के समक्ष अपने क्षेत्र की सार्वजनिक समस्याओं व मांगों को रख सकते हैं और चल रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। साथ ही भविष्य की आवश्यकता क्या है, इसके बारे भी लिखित में जानकारी दे सकते हैं और सीएमओ कार्यालय से जुड़े अधिकारी इन प्रतिवेदनों का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं और संबंधित विभागों को प्रेषित करते हैं। अब तक 16 हजार प्रतिवेदनों की प्रविष्टि की जा चुकी है जबकि 2600 काम पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया है जिसका मूल लक्ष्य लोगों को सरकार की कार्यप्रणाली को समझाना है और आपके माध्यम से जमीनी स्तर तक इस लक्ष्य को पहुँचाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्वच्छ प्रशासन व विकास के कार्य तेजी से हों, यही इस बैठक का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि पहले लोगों को इस बात

साप्ताहिक सूचना पत्र

का संशय रहता था कि चंडीगढ़ मुख्यालय पर फील्ड से भेजे गए प्रतिवेदन केवल फाइलों में दर्ज होते हैं, इस धारणा को खत्म करने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सीधा उच्च अधिकारियों से बातचीत करने के लिए उन्हें एक मंच पर लाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम की शुरुआत की गई।

माननीय जमुख्यमंत्री जी इस मंत्रणा बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों व प्रबुद्ध नागरिकों को अपनी बात रखने के लिए पूरा समय देते हैं। अब तक माननीय मुख्यमंत्री जी सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों को कवर कर चुके हैं, जिसमें आज सिरसा 10वां लोकसभा क्षेत्र था। इस प्रकार 90 विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं को उच्च अधिकारियों ने सीधा सुना है। वर्ष 1966 के बाद माननीय ममुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री बने हैं जिन्होंने यह पहल की है जिसका हेतु उच्च अधिकारियों के साथ प्रबुद्ध नागरिकों का परिचय भी करवाना है ताकि भविष्य में विकास कार्यों की जानकारी सीधे उच्च अधिकारियों को दे सकते हैं।

इन बैठकों के सफल आयोजन के बाद मुख्यमंत्री ने लोगों की मांग पर यह निर्णय लिया है कि इस प्रकार की बैठकें साल में कम से कम 2 बार आयोजित करवाने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही पहले की बैठकों में रखी गई बातों पर हुई कार्रवाई के बारे में भी समीक्षा की जाएगी।

माननीय मामुख्यमंत्री जी ने कहा कि विभिन्न विभागों की ऑनलाइन कार्यप्रणाली लगभग पूरी की जा चुकी है। अब ज्योंही कोई व्यक्ति 60 वर्ष का होता है उसके पास सरकारी कर्मचारी घर जाता है और वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का लाभ देने के लिए उससे सहमति लेता है।अगले महीने ही उसे आटोमेटिक पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। हमने दरख्वास्त ,दस्तावेज व दफ्तर सिस्टम को ऑटोमोड में किया है। अब राशन कार्ड के लिए भी किसी को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। ऑटोमोड से 12.50 लाख नए बीपीएल कार्ड बने हैं। जनसंवाद कार्यक्रमों में भी लोग इस सिस्टम की सराहना कर रहे हैं।

मेधावी छात्र सम्मान समारोह

(दिनांक 16.08.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पंचकुला में अमर उजाला अख़बार की और से आयोजित मेधावी छात्र सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। विद्यार्थियों को शिक्षा के पथ पर आगे बढकर समाज की सेवा का आह्वान करते हुए कहा कि वे जीवन में समाज हित में कुछ विशेष करने का संकल्प लें। इसके साथ ही विद्यार्थी कड़ा परिश्रम करते हुए जीवन में आगे बढ़े और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें।

इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश से आए करीब 160 मेधावी छात्रों को प्रशस्ति पत्र भेंट करते हुए सम्मानित किया। ये विद्यार्थी प्रदेश के विभिनन जिलों से आए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं व 12वीं कक्षा के छात्र थे जिन्होंने परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने विद्यार्थियों से सीधा संवाद करते हुए उनका मार्गदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन में

साप्ताहिक सूचना पत्र

अच्छा मनुष्य बनने के लिए कड़ा परिश्रम करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने जीवन में व्यावहारिक ज्ञान की महत्ता पर बल दिया। विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करते हुए समाज व लोक हित में कार्य करना चाहिए। किसी भी विद्यार्थी की प्रतिभा को निखारने में माता–पिता का सबसे पहला स्थान है। उसके बाद शिक्षकगण इस दिशा में अपनी सर्वोत्तम भूमिका निभाते हैं। इसके बाद मनुष्य के विचार है जो व्यक्ति को निरंतर आगे बढने़ के लिए प्रेरित करते हैं। अच्छा मनुष्य बनने के लिए व्यवहारिक परिश्रम हमें मेधावी बनाता है। अपने जीवन में अभी तक जो भी विद्यार्थियों ने अर्जित किया है वे उसे सीढ़ी बनाते हुए जीवन में निरंतर आगे बढ़े। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे जीवन में इसी प्रकार कठिन परिश्रम करें और निरंतर प्रगति की ओर बढ़ते रहें।

समारोह में माननीय जमुख्यमंत्री जी ने छात्रा आंचल से संवाद किया। आंचल ने मुख्यमंत्री से एनडीए में कैरियर

बनाने संबंधी प्रश्न पूछा जिसका उत्तर देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वे जीवन में जिस भी क्षेत्र का चयन करें उसके लिए पूरी लग्न से तैयारी करें। हो सकता है उन्हें पहले प्रयास में सफलता ना मिले लेकिन निरंतर प्रयासरत रहने से उन्हें निश्चित तौर पर ही सफलता मिलेगी। इसी प्रकार, रोहतक के आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बसाना से आई याशी, रेवाड़ी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मायन से आई नेहा भारद्वाज, जिला सिरसा की छात्रा दिव्या, महेन्द्रगढ़ के नांगल चौधरी के रोहन गुप्ता और फरीदाबाद से इशिका ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से सीधा संवाद करते हुए अपने संशयों को दूर किया।

हरियाणा बिजली विनियामक आयोग गठन की रजत जयंती

(दिनांक 16.08.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के गठन की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित बिजली विनियामक आयोगों के क्षेत्रीय सम्मेलन में मुख्य अथिति शिरकत करते हुए कहा कि राज्यों के बिजली विनियामक आयोगों का जिस उद्देश्य को लेकर का गठन किया गया था उस दिशा में उपभोक्ताओं के हितों में बड़ी सेवा कर रहे हैं तथा अपने स्तर पर बिजली सुधार में सकारात्मक कार्य कर रहे हैं। जिसके फलस्वरूप हरियाणा की सभी बिजली कंपनियां पहली बार मुनाफे में पहुंची हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयोग के गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर बधाई देते हुए कहा कि बिजली डिस्कॉम कंपनियां वित्त क्षेत्र की सबसे बड़े सार्वजनिक उपक्रम में से एक है। बिजली कंपनियों को घाटे से उबारने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल

पर उदय स्कीम लागू की गई थी। हरियाणा सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप बिजली कंपनियों का 25,950 करोड़ रुपये का घाटा सरकार ने अपने स्तर पर वहन किया और आज हरियाणा की सभी चारों बिजली कंपनियां मुनाफे में चल रही हैं।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सर्वप्रथम वर्ष 2014 में जब उन्होंने हरियाणा की सत्ता की बागडोर संभाली थी तो उस समय उन्होंने बिजली सुधार का संकल्प लिया था और वर्ष 2015 में तत्कालीन भिवानी जिले के बाढड़ा में जहाँ बिजली को लेकर बड़े–बड़े आंदोलन हुए, वहां पर आयोजित रैली में उन्होंने उपस्थित लोगों से झोली फैलाकर बिजली के बिल भरने की अपील की थी।

माननीय मुख्यमंत्री जी की अपील का लोगों पर इतना असर हुआ कि लोग स्वयं बिजली के बिल भरने के लिए आगे आ रहे हैं। जिसके फलस्वरूप म्हारा गांव, जगमग गांव योजना के तहत प्रदेश के 5745 गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सम्भव हो पाई है। इतना ही नहीं पिछले 9 वर्षों में बिजली बिलों के रेट भी नहीं बढ़ाये गए हैं।

उन्होंने कहा कि लाइन लॉसेस भी 34 प्रतिशत से घटकर 15 प्रतिशत कम हो गया है। उन्होंने कहा कि लोगों की बिजली पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। कृषि क्षेत्र को सब्सिडी के रूप में बड़ी राशि दी जाती है। हरित ऊर्जा को विकल्प के तौर पर अपनाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं।

पीएम कुसुम योजना के तहत पिछले वर्ष हरियाणा में 53000 कृषि नलकूपों को सौर ऊर्जा पर लाया गया। इस वर्ष 70000 कृषि नलकूपों को सौर ऊर्जा पर लाने का लक्ष्य रखा गया है।

आयोग के चेयरमैन श्री आर के पचनंदा ने अपने स्वागतीय भाषण में कार्यक्रम में पहुँचने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और आयोग की गतिविधियों से अवगत करवाया।

450 अनाधिकृत कालोनियों को नियमति करने की घोषणा

(दिनांक 16.08.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के सूत्र पर चलते हुए शहरों में अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के बड़ी सौगात देते हुए आज 450 अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने की घोषणा की है।

सरकार द्वारा लिया गया यह परिवर्तनकारी निर्णय शहरी विकास, नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने और संगठित व सुव्यवस्थित शहरीकरण को बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इन 450 कॉलोनियों में नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की 239 कालोनियां तथा शहरी स्थानीय निकाय विभाग की 211 कॉलोनियां शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि आज नियमित की गई कालोनियों में पहली बार उन अनधिकृत कालोनियों को भी नियमित किया गया है, जो पालिका क्षेत्रों के बाहर स्थित हैं। ये नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अन्तर्गत आती हैं। ऐसी कॉलोनियों में मूलभूत विकास कार्यों हेतु 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि निमयन उपरांत जो कॉलोनियां पालिका क्षेत्र से बाहर पड़ती हैं, उनके विकास कार्य हरियाणा

ग्रामीण विकास प्राधिकरण द्वारा किए जाएंगे। पालिका के भीतर स्थित कॉलोनियों के विकास कार्य संबंधित नगर पालिका द्वारा किए जाएंगे।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इससे पहले वर्ष 2014 से 2022 तक शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अन्तर्गत आने वाली 685 कालोनियां नियमित की गई थीं। इस प्रकार, आज नियमित होने वाली कॉलोनियों को नियमित करने से वर्ष 2014 से अब तक कुल 1135 अनधिकृत कॉलोनियां नियमित हो जाएंगी।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनधिकृत कॉलोनियों के संबंध में भविष्य की योजना को साझा करते हुए बताया कि वर्तमान में प्रदेश में कुल 1856 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करना विचाराधीन है। इनमें 727 कॉलोनियां नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग तथा 1129 कॉलोनियां शहरी स्थानीय विभाग के अंतर्गत आती हैं। इन कॉलोनियों में मापदण्ड पूरे होने पर इन्हें भी नियमित किया जाएगा। यह राज्य के शहरी नियोजन और विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने कहा कि इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लक्ष्य से नागरिकों की सुविधा के लिए अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने हेतु मानदंडों में छूट दी है। जिन कॉलोनियों तक पहुंचने वाली सड़क 6 मीटर या इससे अधिक तथा आंतरिक सड़कें 3 मीटर या इससे अधिक चौड़ी हैं, अब उन्हें नियमित किया गया है।

माननीय जमुख्यमंत्री जी ने जिला वार कॉलोनियों की जानकारी देते हुए बताया कि फरीदाबाद में 59, फतेहाबाद में 16, गुरुग्राम में 3, हिसार में 20, झज्जर में 25, कैथल में 30, करनाल में 2, कुरुक्षेत्र में 25, नूहं में 35, पलवल में 31, पानीपत में 22, रेवाड़ी में 14, रोहतक में 32, सिरसा में 9, सोनीपत में 35 और यमुनानगर में 92 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया गया है।

हरियाली तीज महोत्सव

(दिनांक 19.08.2023)

प्रभाव : पानीपत के श्री गुरु तेग बहादुर मैदान में आयोजित इस महोत्सव में माननीय मुख्यमंत्री जी और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा ने दीप प्रज्वलित कर तीज उत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोक धुनों पर आधारित सीडी का विमोचन भी किया।

हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित इस राज्य स्तरीय महोत्सव में प्रदेशभर से 50,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लेकर एक रिकॉर्ड कायम किया और यह रिकॉर्ड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी असाधारण छाप छोड़ने वाली 101 महिलाओं को भी सम्मानित किया।

इस अवसर पर उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीज के त्योहार की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपका ये भाई, सुदामा आपके लिए कोथली

लेकर आया है, आप इसे स्वीकार करें, यह मेरी प्रार्थना है। उन्होंने कहा कि हमारी यह परंपरा है कि कोथली के द्वारा भाईयों द्वारा बहनों की सुख समृद्धि का संकल्प लिया जाता है और आज भाई के रूप में मैं आपकी सुख समृद्धि का संकल्प लेता हूं। उन्होंने कहा कि कोई भी त्यौहार माताओं, बहनों और बेटियों के बिना पूरा नहीं हो सकता, महिलाएं हमारे सब त्यौहार का आधार है, इसलिए महिलाओं की सुख शांति के लिए हम संकल्पबद्ध है।

तीज महोत्सव पर महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं

माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीज महोत्सव को और खास बनाते हुए महिलाओं को बड़ी सौगात देते हुए महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों को बेचने के लिए सांझा बाजार की कल्पना पर सभी जिला केंद्रों पर 50 से 100 पोटा कैबिन स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो स्वयं सहायता समूह अपने उत्पाद बनाते हैं, वे अपने उत्पाद बेचने के लिए इन पोटा कैबिन को प्रतिदिन के हिसाब से बुक करवा सकते हैं। माननीय

साप्ताहिक सूचना पत्र

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना व अन्य योजनाओं में 31,000 रुपये से लेकर 71,000 रुपये तक राशि दी जाती है। आज इस न्यूनतम 31,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 41,000 रुपये करने की घोषणा करता हूं।

इसके अलावा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेटियों के लिए एक ओर महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में सरकारी व निजी पॉलिटेक्निक कॉलेज चल रहे हैं, जिनमें डिप्लोमा के कार्स करवाये जाते हैं, उनके इन्फ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग्स ऐसी हैं, जहाँ उनको पर्याप्त ऐडमिशन नहीं मिल रहा है।

ऐसे कॉलेज, जिनके पास इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, अगर वे डिग्री कॉलेज की मांग करेंगे, तो मांग के आधार पर महिलाओं की डिग्री कॉलेज की मंजूरी दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज जिस मैदान पर यह महोत्सव हो रहा है, यह वही मैदान है, जिस पर 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हम सब में अलख जगाकर बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ का संकल्प दिया था। इसी

संकल्प पर कार्य करते हुए प्रदेश सरकार ने सामाजिक सहयोग से हरियाणा पर बेटियों को मारने वाला प्रदेश के नाम से लगे कलंक को मिटाने का काम किया है और उस समय प्रदेश में लिंगानुपात 871 होता था वह आज बढ़कर 927 हो गया है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा की प्रगति बहुत प्रदेशों से काफी अच्छी है। प्रदेश में 57,376 स्वयं सहायता समूह बन चुके हैं। इन्हें 54 करोड़ 57 लाख रुपये रिवोलविंग फण्ड, लगभग 285 करोड़ रुपये सामुदायिक निवेश फण्ड और लगभग 880 करोड़ रुपये बैंक क्रेडिट लिंकेज प्रदान किया गया है। इतना ही नहीं, हमने रिवोलविंग फण्ड की राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये की है। महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपये तक ऋण लेने पर स्टाम्प शुल्क से छूट भी दी गई है।

महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित चीजों की प्रदर्शनी को देखकर माननीय मुख्यमंत्री जी

भाव–विभोर हुए और कहा कि यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में हमारी महिलाओं की एक सराहनीय पहल है।

तीज महोत्सव पर आयोजित यह कार्यक्रम हरियाणवी खानपान, परिधान और पहचान का साक्षी बना है। महिलाओं के साथ साथ छोटे बच्चे भी हरियाणवी परिधान में इस कार्यक्रम में पहुंचे और कार्यक्रम का जमकर आनंद लिया। सबसे खास बात यह रही कि उत्सव में 101 झूलों की झूल डाली गई और महिलाओं के पारंपरिक रूप से कोथली तैयार की गई। समारोह में पदमश्री सुमित्रा गुहा ने राग मल्हार की प्रस्तुति दी और सावन की ऋतु आई सखी री३ लोक गीत गाकर समा बांध दिया। इसके अलावा, मीनाक्षी पांचाल ने भी सावन गीत की प्रस्तुति दी। पूरा पंडाल लोक गीतों के रंग में रंगा नजर आया और आम महिलाओं के साथ साथ महिला अधिकारियों ने भी हरियाणवी

गीतों पर ठुमके लगाए। महिलाओं ने विशेष रूप से तैयार गुलगुले, सुहाली और पतासे जैसे पारंपरिक खानपान का आनंद लिया।

हरियाणा में पहली बार मनाए गए राजकीय तीज महोत्सव में 101 महिला अचीवर्स को सम्मानित भी किया गया। सही मायनों में हरियाणवी संस्कृति को सहजने और संजोने के प्रयासों को सरकार ने और गति दी है और इस प्रकार के कार्यक्रमों से त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने की हमारी पुरानी परंपरा को भी बल मिलेगा।

भावांतर भरपाई योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद

(दिनांक 19.08.2023)

प्रभाव : गुरुग्राम से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भावांतर भरपाई योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम की शुरुआत से आज तक अलग–अलग योजनाओं के माध्यम से किसानों से यह आठवीं बार संवाद हो रहा है।

किसानों की खुशहाली में ही प्रदेश और राष्ट्र की खुशहाली निहित है, इसलिए खेती और किसान हरियाणा सरकार की नीतियों के केंद्र में हैं। सरकार फसलों के तैयार होने से लेकर बाजार में उसकी बिक्री तक किसानों को हर संभव सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं।

इसी कड़ी में किसानों को जोखिम मुक्त बनाने के लिए सरकार ने भावांतर भरपाई योजना शुरू की। इस योजना के तहत अब तक फल व सब्जी उत्पादक 12 हजार से अधिक किसानों को 33 करोड़ 26 लाख रुपये की राशि दी गई है।

संवाद के दौरान किसानों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि भावांतर भरपाई योजना लाकर हरियाणा सरकार ने सही मायनों में हमें सहारा देने का काम किया है। पहले हमें मंडियों में बाजार भाव से नीचे चले जाने पर भी अपनी उपज को कम दामों में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता था, लेकिन इस योजना के बाद से हम आश्वस्त रहते हैं कि बाजार भाव के नीचे चले जाने के बाद भी सरकार हमारी सहायता करेगी।

वर्तमान समय की जरूरत के हिसाब से खेती में नए व सफल प्रयोग करने वाले किसानों ने साहसिक कार्य किया है। आपकी सफलता से अन्य किसानों को भी प्रेरणा मिली है और खेती में गेहूं व धान के चक्र से बाहर निकलकर बाजार

साप्ताहिक सूचना पत्र

की मांग के अनुसार फसलें बोने लगे हैं। किसान फसल तो पैदा कर लेता है, लेकिन उसके सामने बाजार भावों की अनिश्चितता बनी रहती थी और कई बार तो कम कीमत पर फसल बेचने को मजबूर होते थे। किसानों की इस समस्या को हमने समझा और तय किया है कि फसल बोने से पहले ही किसानों को यह पता चल जाए कि फसल का कम से कम एक सुनिश्चित मूल्य तो मिलेगा ही। इसके लिए राज्य सरकार ने फल व सब्जियों के लिए जनवरी, 2018 से तथा बाजरे के लिए खरीफ–2021 से भावांतर भरपाई योजना शुरू की है।

जिन किसानों से बात हो रही है, उनमें बाजरा पैदा करने वाले किसान भी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। मोटे अनाज सेहत के लिए अच्छे हैं, इसलिए आज सेहत के लिए जागरूक लोगों में इनका सेवन करने का रुझान बढ़ा है और इनकी मांग न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी बढ़ी है। हम हरियाणा में भी मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं और किसान को भी इनके लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किये हैं।

भावांतर की भरपाई बाजरे की प्रति एकड़ औसत उत्पादकता के आधार पर की गई है। यदि किसान अच्छे भाव मिलने के इंतजार में अपनी उपज मंडी में नहीं लाया तो भी, यदि उसने अपने उपयोग के लिए बाजरा रख लिया तो भी उसे भावांतर का भुगतान किया जाता है। खरीफ सीजन–2021 में बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,250 रुपये प्रति क्विंटल था और औसत बाजार भाव 1650 रुपये प्रति क्विंटल था। हमने 600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भावांतर भरपाई की। खरीफ–2021 में 2 लाख 42 हजार 948 किसानों के खातों में 440 करोड़ रुपये की राशि भावांतर भरपाई के रूप में सीधी डाली गई। खरीफ–2022 में बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,350 रुपये प्रति क्विंटल था और औसत

साप्ताहिक सूचना पत्र

बाजार भाव 1900 रुपये प्रति क्विंटल था। हमने 450 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भावांतर भरपाई की। खरीफ–2022 में 2 लाख 76 हजार 620 किसानों के खातों में 390 करोड़ रुपये की राशि भावांतर भरपाई के रूप में सीधी डाली गई। इस प्रकार दो सीजन में बाजरे की पैदावार करने वाले किसानों के खाते में 830 करोड़ रुपये सीधे ही डाले गये।

भूमि जोत छोटी होती जा रही है। छोटी होती भूमि जोत को लाभकारी बनाने का एक ही तरीका है कि किसान बागवानी की ओर अग्रसर हों और फलों, सब्जियों और फूलों की खेती को अपनाएं। हमारा लक्ष्य वर्ष 2030 तक बागवानी के अधीन क्षेत्र को दो गुणा करके 22 लाख एकड़ करने तथा उत्पादन को तीन गुणा करने का है। मुझे विश्वास है कि आप जैसे जागरूक किसानों के सहयोग से हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेंगे।

राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि बागवानी किसानों को बाजार भावों के उतार–चढ़ाव की मार न झेलनी पड़े, इसके लिए भावांतर भरपाई योजना के

तहत बागवानी फसलों के लिए संरक्षित मूल्य निर्धारित किया है। इस व्यवस्था से किसान को बिजाई के समय ही यह पता चल जाता है कि उसे प्रति एकड़ कितनी आय होगी।

किसानों को मौसम के कारण भी फसलों में भारी नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिए सरकार ने मौसम की अनिश्चितताओं के जोखिम से किसानों को मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की है। इसमें बागवानी की 21 फसलें शामिल हैं। इसमें सब्जियों के लिए 75,000 रुपये और फलों के लिए 1 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर क्लेम राशि दी जा रही है। एक समय था जब किसान अपनी फसल बेचता था, तो उसे अपने हक का पैसा नहीं मिलता था। पैसा किसी और के खाते में जाता था और उनको अपने खर्च के लिए समय समय पर किसी के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे। लेकिन हमारी सरकार ने इस प्रथा को बंद किया और किसानों के खाते में डीबीटी

के माध्यम से लगभग 50,000 करोड़ रुपये सीधे उनके खातों में डाले हैं। अब किसान अपनी फसल बेच कर आता है तो पैसा सीधा उसके खाते में पहुंचता है। उन्होंने किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 6000 रुपये की सहायता दिये जाने के लिए भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया।